शिपिंग कारपोरेशन को मिलेगा 500 करोड़ रुपये: गडकरी

मुंबई, 6 जुलाई (ए)। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार शिपिंग कारपोरेशन को

जहाज खरीदने और घरेलू स्तर पर उसे पट्टे पर देने को लेकर 500 करोड़ रुपये देगी। उद्योग के एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा, ''हम सागरमाला कार्यक्रम के तहत शिपिंग कारपोरेशन (एससीआई) को 500 करोड़ देंगे। यह राशि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सस्ते जहाज खरीदने के लिये दी जाएगी।'' उन्होंने कहा कि सावर्जनिक क्षेत्र की एससीआई घरेलू बाजार में उन निजी पक्षों को ये विमान पट्टे पर देगी जिन्हें पूंजी जुटाने में कठिनाई हो रही है लेकिन वे इसे उत्पादक कार्यों के लिये इसका उपयोग कर सकते हैं। उन जहाजों का उपयोग क्रूज पर्यटन, वाहनों एवं अन्य माल की ढुलाई के लिये ' रोल आन रोल आफ ' सेवा आदि में किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गडकरी ने कहा कि सड़क यातायात को समुद्र की ओर मोड़ने की जरूरत है और हमें अंतरराष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाना है जहां फिलहाल जहाज सस्ते में उपलब्ध है। स्वच्छ ईंधन की बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मेथेनाल और एथेनाल जैसे ईंधन के उपयोग की जरूरत है। यह आयातित ईंधन का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स महाराष्ट्र के थाल में ऐसे ईंधन के उत्पादन के लिये इकाई लगा रही है।

ब्रेक्जिट से नुकसान हुआ तो ब्रिटेन छोड़ देगी जेएलआर

लंदन, 6 जुलाई (ए)। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने ब्रिटेन की सरकार को चेतावनी दी है कि खराब ब्रेक्जिट डील से उसकी निवेश योजनाएं खटाई में पड़ सकती हैं। इससे उसे हर साल करीब 1.2 अरब पौंड (11000 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा। ऐसे हालात में उसे अपने प्लांट बंद करके ब्रिटेन से बाहर जाना होगा। जगुआर लैंड रोवर ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। ब्रिटेन अगले साल मार्च में 28 देशों के यूरोपियन यूनियन (ईयू) से बाहर हो जाएगा। इसके साथ उसका ईयू से 40 साल पुराना नाता टूट जाएगा। जेएलआर के सीईओ राल्फ स्पेथ ने बुधवार को एक बयान जारी करके चेतावनी दी कि ब्रेक्जिट की नुकसानदायक शर्तों से कंपनी का सालाना खर्च 1.2 अरब पौंड से ज्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से उसे अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ सकती है। स्पेथ का यह बयान ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे और उनके मंत्रिमंडल की शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले आया है। इस बैठक में ब्रेक्जिट के बाद ईयू के साथ सीमा शुल्क संबंधी शर्तों पर विचार किया जाना है। जेएलआर के सीईओ ने कहा कि वह किसी को धमकी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हमें समझौते की शर्तों के असर को लेकर पारदर्शी रहना चाहिए। हम ब्रिटेन में रहना चाहते हैं। जेएलआर का दिल और आत्मा ब्रिटेन में ही बसती है। ब्रिटेन में आगामी निवेश जारी रखने के लिए हम ज्यादा आश्वास्त होना चाहते हैं कि हमारे सप्लायर, ग्राहकों और ब्रिटेन में 40,000 कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी।

हाईकोर्ट ने वोडाफोन की अपील पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली , 6 जुलाई (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। वोडाफोन ने इस याचिका में उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास कंपनी द्वारा भारत के खिलाफ शुरू की गयी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर अपील की सुनवाई का अधिकार है। वोडाफोन ने 11,000 करोड़ रुपये की कर मांग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू की है। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी तथा न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने वोडाफोन की ओर से दायर आपत्ति पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। वोडाफोन ने सरकार की एकल जज के सात मई के आदेश के खिलाफ लंबित अपील पर अपनी आपत्ति जतायी है. सरकार ने एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने की उसकी अपील को खारिज करने को चुनौती दी गयी है। पीठ ने वोडाफोन की याचिका और केंद्र की अपील को 11 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा

नई दिल्ली, 6 जुलाई (ए)। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बीते एक माह बाद बीते दिन पहली बार इजाफा हुआ था। 14 से 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतें 75.71 रुपये प्रति लीटर है। अन्य मेट्रो शहरों की बात करें तो मुंबई में 83.24 रुपये, कोलकता में 78.53 रुपये और चेन्नई में 78.72 रुपये प्रति लीटर के भाव से पेट्रोल बिक रहा है। इसी तरह डीजल की बात करें तो इसमें भी आज 16 से 18 पैसे की तेजी हुई है।

रिलायंस शुरू करेगी फाइबर ब्राडबैंड सेवा, ई-कॉमर्स में भी उतरने की तैयारी

मुंबई, 6 जुलाई (ए)। नि:शुल्क कॉलिंग और सस्ती दर पर तीव्र मोबाइल इंटरनेट सेवा की पेशकश से भारत के दूरसंचार उद्योग की सूरत बदलने वाले देश के सबसे धनी व्यक्ति एवं रिलायंस उद्योग समूह के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 1100 शहरों में 'हाईस्पीड' फिक्स्ड लाइन ब्राडबैंड सेवा शुरू करने की आज घोषणा की। उन्होंने ई-कॉमर्स क्षेत्र में उतरने की योजना की भी घोषणा की। अंबानी ने कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से कहा कि ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन जैसे पुराने कारोबार को मजबूत करने के साथ साथ नये क्षेत्रों में कारोबार के विस्तार से समूह की आय 2025 तक दो गुना कर 125 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 'जियो गीगाफाइबर सर्विस' के लिए 15 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने सेवा की शुरुआत के समय के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस सेवा के तहत एक ही फाइबर केबल के जरिये टेलीविजन पर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इंटरटेनमेंट, वॉयस एक्टिवेटेड असिस्टेंस, वर्चुअल रियल्टी गेमिंग, डिजिटल

शॉपिंग आदि समेत स्मार्ट होम समाधान भी मुहैया कराये जाएंगे। उन्होंने कहा, ''अब हम 1100 शहरों में घरों, व्यापारियों, छोटे एवं मध्यम उद्योगों और बड़े उद्योगों को सबको एक साथ फाइबर से जोड़ेंगे और सर्वाधिक उन्नत फाइबर-बेस्ड ब्राडबैंड समाधान मुहैया कराएंगे।'' अंबानी ने कहा कि आने वाले सालों में जियो फिक्स्ड लाइन ब्राडबैंड के मामले में भारत को शीर्ष पांच देशों में से एक बना देगी। उन्होंने इस सेवा की दरों की भी जानकारी नहीं दी।

उन्होंने कहा, ''हम अभी हजारों घरों में इसका बीटा परीक्षण कर रहे हैं। जहां भारत मोबाइल ब्राडबैंड के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, वहीं हम फिक्स्ड-लाइन ब्राडबैंड में काफी पीछे हैं। इस मामले में वैश्विक आधार पर हम 134वें स्थान पर हैं। फिक्स्ड लाइन में खराब ढांचागत संरचना इसका मुख्य कारण है।'' उन्होंने कहा कि देश भर में मोबाइल एवं ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संरचना पहल पर पहले ही 2,50,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है। अब घरों तक फाइबर ब्राडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचेगा।

सितंबर 2016 में शुरुआत के बाद जियो ने देश को सबसे अधिक मोबाइल डेटा की खपत करने वाला देश बना दिया। अंबानी ने कहा कि जियो के ग्राहकों की संख्या 21.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है जबकि उसने अब तक 2.5 करोड़ से अधिक जियो फोन बेचे हैं। अंबानी ने कम से कम समय में 10 करोड़ जियो फोन उपभोक्ता का भी लक्ष्य तय किया। उन्होंने जियो फोन मानसून हंगामा शुरू करने की भी घोषणा की। यह योजना 21 जुलाई से शुरू होगी और इसके तहत महज 501 रुपये में फीचर फोन के बदले जियो फोन लिया जा सकेगा। उन्होंने दूसरी पीढ़ी के जियोफोन की भी घोषणा की। इसमें फेसबुक, व्हाट्सऐप और यूट्यूब भी होंगे। इसकी बुकिंग 2,999 रुपये में 15 अगस्त से की जा सकेगी।

अंबानी ने कहा रिलायंस कंपनी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कारोबार विस्तार करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता कारोबार भी ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन कारोबार की तरह योगदान देने वाला है। अंबानी ने कहा, भारत जब उच्च गति से आर्थिक वृद्धि की यात्रा शुरू करने वाला है और 2025 तक अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने वाला है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस अवधि में रिलायंस का आकार दोगुने से अधिक होगा।'' उन्होंने कहा कि जियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। उन्होंने कहा जियो के कारण देश की डेटा खपत 128 करोड़ जीबी प्रति माह से बढ़कर 240 करोड़ जीबी प्रति माह से भी आगे निकल गयी है। अंबानी ने कहा कि कंपनी ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, जैसा कि रिलायंस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कंपनी बनते जा रही है, हमें वृद्धि के सर्वाधिक अवसर एक हाइब्रिड यानी ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने में दिखते हैं।'' उन्होंने कहा, हम रिलायंस रिटेल के बाजार को जियो की डिजिटल संरचना एवं सेवा से जोड़कर ऐसा कर सकेंगे।''

कंपनी के पारंपरिक कारोबार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिलायंस विश्व के सबसे बड़े पैराक्सिलीन संयंत्र, पेटकोक गैसीफिकेशन संयंत्र और ऑफ-गैस क्रैकर की शुरुआत करने के साथ ही अपना सबसे बड़ा निवेश पूरा करने वाली है।

वालमार्ट और अमेजन को टक्कर देने की तैयारी में रिलायंस

नई दिल्ली,6 जुलाई (ए)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी सालाना आम बैठक (एजीएम) ऐसी बात कही है जिसके बाद अमेजन और वालमार्ट को कड़ी टक्कर मिल सकती है। अंबानी ने इस बात की घोषणा की है कि कंपनी आने वाले समय में ऑनलाइन मार्केटप्लेस खोलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया है कि आरआइएल की ऑनलाइन और रिटेल दोनों पर उपस्थिति है ऐसे में कंपनी इन्हें मिलाकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की योजना पर काम कर रही है। हाल ही में वालमार्ट ने भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया है। वहीं दूसरी ओर अमेजन ने भारत में कारोबार विस्तार की योजना बनाई है। अंबानी की इस नई योजना से वालमार्ट और अमेजन दोनों को कड़ा मुकाबला मिलना निश्चित है। मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को अपनी इस योजना के बारे में गुरुवार को जानकारी दी थी। बता दें कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने में रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड शामिल होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्लानिंग ऑनलाइन टू ऑफलाइन रिटेल शुरू करने की है। इसे समूह की टेलिकॉम सर्विस और 7500 रिटेल स्टोर्स के साथ मिलाकर तैयार किया जाएगा।

मोबाइल ऐप बताएगा बिल में जुड़े जीएसटी की वैधता

नई दिल्ली, 6 जुलाई (ए)। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुकानदार या रेस्तरां संचालक आपसे सामान या खाने के बिल के साथ जीएसटी वसूल की मांग कह रहा है, वह वैध है भी या नहीं। आपने जो जीएसटी का भुगतान किया है, वह सरकार के खाते में जमा होगा या नहीं। अब एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये आप यह चैक कर सकेंगे कि जिस व्यापारी से आप खरीदारी कर रहे हैं, उसे जीएसटी वसूलने का अधिकार है भी या नहीं। ऐप के जरिये फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारी की शिकायत भी की जा सकती है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बी. रघु किरण ने जीएसटी वैरीफाई नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसके जरिये आप इसकी जांच कर सकते हैं। तेलंगाना के मेदचल जीएसटी कमिश्नरेट में संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात किरण ने बताया कि जब भी आप कुछ खरीददारी करने जाते हैं या रेस्तरां में खाना खाते हैं तो आपके बिल में जीएसटी अलग से जुड़ा आता है। ऐसे में अगर आप यह चैक कर लेते हैं कि वह दुकानदार या रेस्तरां आपसे जीएसटी वसूलने का हकदार है या नहीं तो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इससे आपका पैसा बचेगा। किरण ने कहा कि यह एप्लीकेशन एक जुलाई को जीएसटी दिवस के अवसर पर लांच किया गया। यह ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और अब तक इसे 20 हजार से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। मोबाइल में जीएसटी वैरीफाई एप डाउनलोड करने के बाद कोई भी व्यापारी का 15 अंकों का जीएसटीएन नंबर डालकर इसमें चैक कर सकता है कि वह व्यापारी किस श्रेणी में पंजीकृत है और उस व्यापारी को ग्राहक से टैक्स वसूलने का अधिकार है या नहीं।

किसी भी पुराने फीचर फोन के बदले 501 रुपये में मिलेगा जियोफोन

नई दिल्ली, 6 जुलाई (ए)। रिलायंस जियो ने फीचर फोन उपभोक्ताओं के लिए जियो फोन मानसून हंगामा नाम से नई स्कीम का एलान किया है। इसके तहत जियो ग्राहक किसी भी पुराने फीचर फोन (किसी भी कंपनी का सामान्य मोबाइल फोन) के बदले 501 रुपये की कीमत में नया जियो फोन पा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी 15 अगस्त से 2999 रुपये की शुरुआती कीमत पर जियो फोन-2 का ऑफर भी देने जा रही है।

जियो की मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पुत्री ईशा और पुत्र आकाश अंबानी ने कंपनी की 41वीं सालाना आम बैठक में जियो फोन-2 लांच किया। यह फोन बाजार में 15 अगस्त से मिलेगा। किसी भी फीचर फोन के बदले 501 रुपये देकर जियोफोन-1 लेने की सुविधा 21 जुलाई से उपलब्ध होगी। जियो फोन के दस करोड़ नए ग्राहक बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ 1100 शहरों में घरों, कारोबारियों, छोटे, मझोले और बड़े उद्यमों के लिए सबसे एडवांस फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रदान करने का एलान किया।

आम बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत में अभी भी फीचर फोन के ग्राहक बड़ी संख्या में हैं। अभी भी 50 करोड़ भारतीय फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केवल 22 महीनों में जियो का ग्राहक आधार बढ़कर 21.50 करोड़ हो गया है। इसमें जियो फोन के ढाई करोड़ ग्राहक शामिल हैं। यह ऐसा रिकॉर्ड है जिसे विश्व की कोई भी कंपनी हासिल नहीं कर सकी है। अब हम जियो फोन की क्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाकर अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि 15 वर्ष पहले रिलायंस इन्फोकॉम ने मानसून हंगामा ऑफर देकर 500 रुपये में फोन लांच किया था।

जियो गीगा फाइबर सेवा उन्होंने कहा कि 1100 शहरों में एडवांस फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के तहत व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड के जरिये घरों और दफ्तरों में बड़े स्क्रीन पर अल्ट्रा हाई डेफिनिशन एंटरटेनमेंट, लिविंग रूम में मल्टी पार्टी वीडियो कांफ्रेंसिंग, वॉइस-एक्टिव वर्चुअल असिस्टेंस तथा वर्चुअल रियलिटी गेमिंग और डिजिटल शॉपिंग की सुविधा मिलेगी।

ट्रेड वार और महंगे क्रूड से बिगड़ सकती है रुपये की हालत, जारी रह सकती है गिरावट

नई दिल्ली, 6 जुलाई (ए)। वैश्विक ट्रेड वार की गहराती चिंताएं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपये अगले एक साल तक और कमजोर हो सकता है। यह बात रॉयटर के पोल में सामने आई है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह भारतीय रुपये ने एतिहासिक निम्नतम स्तर छुआ था। हालांकि आर्थिक विकास ने रफ्तार पकड़ी है और भारत ने इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा बरकरार रखा है, लेकिन फिर भी बीते हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपये ने 69.09 का स्तर छुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रहा है।

डॉलर के मुकाबले भारतीय

रुपये में इस साल अबतक सात फीसद तक कि गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इस कमजोरी के मुख्य कारण उभरते बाजार में बढ़ती बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे लगातार इजाफे से चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। भारत की ओर से आयात किये जाने वाली सबसे बड़ी चीज कच्चा तेल है।

दो जुलाई से पांच जुलाई, 2018 के बीच हुए पोल में 45 रणनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया था। उनका अनुमान है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जून 2019 तक 68.90 के स्तर पर पहुंचेगा, जो कि जून के आखिरी बुधवार के बंद स्तर 68.69 से मामूली सा ही कम है। बीते एक महीने में ग्लोबल ट्रेड वार का तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। यूएस क्रूड फ्यूचर्स में एक जून से अबतक 13 फीसद की बढ़त देखने को मिली है और बुधवार को यह साढ़े तीन वर्ष के उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रहा था।

यस बैंक को मिली मंजूरी, अब बेच सकेगा म्युचुअल फंड यूनिट्स

नई दिल्ली, 6 जुलाई (ए)। यस बैंक को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को म्युचुअल फंड बिजनेस के लिए मंजूरी मिल गई है। बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यह अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से यस बैंक को म्युचुअल फंड स्पॉन्सर किए जाने के बाद मिला है। सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने बाद यस बैंक अब म्युचुअल फंड बिजनेस शुरू कर सकेगी। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राना कपूर ने बताया, यस एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) लिमिटेड (वाईएएमआईएल) यस बैंक के नॉलेज बैंकिंग एक्सपर्टिज और रिटेल, कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैपिटल का इक्विटी और डेट केपिटल मार्केट में बेहतर ढंग से अपनी संपत्ति को प्रभावी बनाने का लाभ उठाएगा। कपूर ने आगे बताया कि यह रणनीतिक पहल बैंक की रिटेल देनदारियों और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी रणनीतियों को को आगे बढ़ाएगी और इसके साथ ही यस एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) लिमिटेड के ग्राहकों को बेरोक-टोक निवेश और बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निर्माण करेगी। आगे बैंक ने यह भी बताया कि उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टी के गाइडेंस में ऑपरेशंस स्थापित करने के लिए एक टीम का गठन भी किया है। साथ ही बैंक ने यह जानकारी भी दी कि यस एसेट मैनेजमेंट अगले 6 से 12 महीनों के भीतर डेट और इक्विटी मार्केट में फंड ऑफरिंग लॉन्च करेगा।

विजय माल्या की संपत्तियों की नीलामी से एसबीआइ ने वसूले 963 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, 6 जुलाई (ए)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के महाप्रबंधक अरिजित बसु ने शुक्रवार को कहा कि विजय माल्या की संपत्तियों की नीलामी से हमने 963 करोड़ रुपये वसूले हैं। आगे उन्होंने कहा कि माल्या से वसूली के आदेश को लागू करने संबंधी ब्रिटेन की अदालत के आदेश से खुशी हुई है, पूरा पैसा वसूलने की उम्मीद बढ़ी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या से बकाया की वसूली का प्रयास कर रहे भारत के 13 बैंकों के गठजोड़ के पक्ष में निर्णय लागू कराने के लिए प्रवर्तन का आदेश जारी किया है। माल्या पर बैंकों के साथ कर्ज में 9 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध कर रहे हैं। इस आदेश के तहत ब्रिटेन उच्च न्यायालय के प्रवर्तन अधिकारी को माल्या की लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में संपत्तियों में प्रवेश की अनुमति दी गयी है। इसके तहत अधिकारी और उसके एजेंट को ब्रिटेन के वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक और ब्रैंबल लॉज में उनके ठिकानों में प्रवेश की

अनुमति होगी। माल्या इस समय वहीं हैं। यहां चर्चा कर दें कि एजेंटों को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा। हालांकि, यह प्रवेश का निर्देश नहीं है। इसका मतलब है कि बैंकों के लिए यह एक साधन है जिसका इस्तेमाल वे करीब 1.14 अरब पाउंड की वसूली के लिए कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय का प्रवर्तन अधिकार या उसके तहत कोई प्रवर्तन एजेंट जरूरी होने पर संपत्ति में प्रवेश के लिए पर्याप्त बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से गुरुवार को कहा कि उसने शराब व्यवसायी विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। लेकिन फेरा उल्लंघन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में पुलिस इनमें से कोई संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी है। बेंगलुरु पुलिस ने इडी के जरिये मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत को बताया कि वह माल्या की संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी, क्योंकि इनमें से कुछ को मुंबई क्षेत्र के ईडी ने कुर्क कर लिया है और शेष संपत्ति परिसमापन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।